भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 924
बुधवार, 26 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हीट एक्शन प्लान (एचएपी)

924. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों में भारत में गर्मी के कारण कुल कितनी मोतें हुईं;
(ख) क्या सरकार केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय हेतु व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत हीट एक्शन प्लान (एचएपी) लाने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा हीट एक्शन प्लान की सर्वाधिक आवश्यकता वाले राज्यों और शहरों में संबद्ध प्राधिकरण के अंतर्गत इसके निर्माण हेतु परिकल्पित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या एचएपी के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी संस्थानों को पर्याप्त धनराशि प्राप्त होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी संसाधन आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017-2021 की अवधि के दौरान देश में लू के कारण होने वाली मौतों की संख्या,**अनुलग्नक-I** में दी गई है। यह देखा जा सकता है कि हाल के वर्षों में लू के कारण होने वाली मौतों की संख्या में काफी कमी आयी है। मौतों की संख्या में कमी आने के कारणों में से एक कारण यह है कि अब लू के लिए बेहतर पूर्व चेतावनी सेवाएं (दिशानिर्देश के साथ) उपलब्ध करायी जाती हैं।

(ख)-(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई हिस्सों में **हीट एक्शन प्लान** शुरू किया है, ताकि लू के बारे में अग्रिम में चेतावनी दी जा सके और साथ ही ऐसी स्थितियों के दौरान की जाने वाली कार्रवाई के बारे में परामर्श दिया जा सके।

हीट एक्शन प्लान वर्ष 2013 में संचालन में लाया गया, यह चरम लू घटनाओं के लिए एक व्यापक पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा तैयारी योजना है। यह योजना संवेदनशील जनसंख्या पर अत्यधिक लू के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी बढाने, सूचना साझा करने तथा प्रत्युत्तर समन्वयन के लिए तत्काल कार्यवाही के साथ-साथ दीर्घकालिक कार्यवाही को प्रस्तुत करता है। हीट एक्शन प्लान विकसित करने के लिए एनडीएमए तथा आईएमडी 23 ऐसे राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, जहां पर प्राय: उच्च तापमान होने के कारण लू चलती है।

1. आंध्र प्रदेश
2. अरुणाचल प्रदेश
3. बिहार
4. छत्तीसगढ़
5. दिल्ली
6. गुजरात
7. गोवा
8. हरियाणा
9. हिमाचल प्रदेश
10. झारखंड
11. जम्मू एवं कश्मीर
12. कर्नाटक
13. केरल
14. महाराष्ट्र
15. मध्य प्रदेश
16. ओडिशा
17. पंजाब
18. राजस्थान
19. तमिलनाडु
20. तेलंगाना
21. उत्तराखण्ड
22. उत्तर प्रदेश
23. पश्चिम बंगाल

हीट एक्शन प्लान के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:;

- पूर्वानुमानित उच्च एवं चरम तापमान के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा इंटर-इजेंसी समन्वयन स्थापित करना। प्रमुख विभागों, विशेष रूप से स्वास्थ विभाग के लोगों एवं इकाईयों को स्पष्ट कर देना कि कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, कब करेगा, और कैसे करेगा।
- लू-संबंधी रोग, विशेष रूप से प्रचंड लू वाली घटनाओं को पहचानने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए स्थानीय स्तर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण कार्यक्रम। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में चिकित्सा अधिकारियों, पैरामेडिकल कर्मचारियों, तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, ताकि वे मृत्यु और बीमारी कम करने के लिए लू-संबंधी चिकित्सीय समस्याओं की प्रभावी तरीके से रोकथाम एवं प्रबंधन कर सकें।
- सार्वजनिक जागरुकता तथा सामुदायिक पहुंच के माध्यम से लोगों तक जागरुकता संदेश पहुंचाये जाते हैं कि उन्हें प्रचंड लू से कैसे बचाव करना है, ये संदेश प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, तथा सोशल मीडिया और सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्रियों जैसे कि पैम्फलेट, पोस्टर, तथा विज्ञापन एवं टेलीविजन कॉमर्शियल (TVCs) के माध्यम से पहुंचाये जाते हैं, तथा इनमें लू संबंधित रोगों के लिए करने एवं न करने वाले कार्य तथा उपचार उपाय बताये जाते हैं।
- गैर-सरकारी तथा सिविल सोसायटी के साथ सहयोग: गैर-सरकारी संगठनों तथा सिविल सोसायटी संगठनों के साथ सहयोग किया जाता है ताकि जहां जरूरत हो वहां बस स्टैंड, बिल्डिंग पर अस्थायी शेल्टर को सुधारा जा सके, सार्वजनिक क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके, तथा लू की समस्या से निपटने के लिए अन्य नवप्रवर्तनशील उपाय किये जा सकें।

- संवेदनशील समूहों, तथा प्रत्येक समूह के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान करना।
- प्रभावी रणनीतियां, एजेंसी समन्वयन, तथा प्रतिक्रिया नियोजन का विकास करना, जो लू के कारण स्वास्थ्य को होने वाले जोखिमों का समाधान कर सके।
- मानव स्वास्थ्य पर लू के प्रभाव की निगरानी एवं मूल्यांकन करने के लिए हीट हेल्थ इंफॉरमेशन सर्विलांस सिस्टम (HHISS)।
- नए प्रयासों के माध्यम से लू के संपर्क को कम करना तथा अनुकूलन उपायों को बढ़ावा देना, जिसमें उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की मैपिंग करना, प्रचंड लू वाले दिनों के दौरान पेय जल तथा ठंडी जगहें उपलब्ध करवाना।
- बचने हीट एक्शन प्लान का नियमित रूप से मूल्यांकन एवं अद्यतन करना।

लू से बचने के लिए एक पहल **के रूप में,** आईएमडी, नियोजन उद्देश्यों के लिए, वर्ष 2016 से, मार्च के अंतिम सप्ताह में अप्रैल, मई एवं जून के महीने में तापमान के लिए मौसमी पूर्वानुमान जारी करता आ रहा है। हाल के वर्षों में, IMD ने मार्च से मई के दौरान तापमान का मौसमी पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया है, जो कि हर माह के अंत में अगले माह के लिए जारी किये जाने वाले मासिक पूर्वानुमान के अलावा है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने हाल ही में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स आरंभ किया है।

हीट इंटेक्स उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव और इस प्रकार लोगों को अनुभूत वाले तापमान के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसे मानव असहजता के लिए एक संकेत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यह, असहजता कम करने और स्वयं को शीतल रखने के लिए लोगों द्वारा उठाये जा सकने वाले अतिरिक्त देखभाल उपायों की जानकारी प्रदान करता है।

(ङ) हीट एक्शन प्लान में मौसम एवं जलवायु संबंधी पूर्वानुमान एवं चेतावनियों के कार्यान्वयन के लिए IMD को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से निधि आवंटित की जाती है।

अनुलग्नक-I

वर्ष 2017-2021 के दौरान लू / सन स्ट्रोक के कारण दुर्घटनावश होने वाली मौतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2017	2018	2019	2020	2021
1	आंध्र प्रदेश	231	97	128	50	22
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	3	0	0
4	बिहार	84	64	215	53	57
5	छत्तीसगढ़	11	1	16	3	2
6	गोवा :	0	0	0	0	0
7	गुजरात	25	31	27	12	8
8	हरियाणा	24	56	46	23	14
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1
10	झारखंड	51	42	88	23	33
11	कर्नाटक	0	0	4	1	0
12	केरल	1	1	3	0	0
13	मध्य प्रदेश	34	15	33	7	2
14	महाराष्ट्र	102	128	159	56	37
15	मणिपुर	0	0	0	0	0
16	मेघालय	0	4	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	99	40	84	13	15
20	पंजाब	60	38	90	110	91
21	राजस्थान	35	43	54	23	1
22	सिक्किम	0	0	1	0	0
23	तमिलनाडु	0	0	0	0	2
24	तेलंगाना	180	107	156	98	43
25	त्रिपुरा	0	1	1	2	0

26	उत्तर प्रदेश	142	176	117	50	35
27	उत्तराखण्ड	0	0	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	48	46	49	6	11
	कुल राज्य	**1127**	**890**	**1274**	**530**	**374**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
31	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0	0	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	0	0	0
33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	0	0	0	0	0
34	लद्दाख @	-	-	-	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल (समस्त भारत)	**1127**	**890**	**1274**	**530**	**374**

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार

स्रोत: भारत में दुर्घटना और आत्महत्या के कारण मृत्यु

'+' वर्ष 2017-2019 के दौरान भूतपूर्व दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2017-2019 के दौरान भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य समेत लद्दाख का आंकड़ा

'@' नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र का आंकड़ा